

व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।

- (iv) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार कर ली जाएगी ताकि गृह क्षति अनुदान का भुगतान हो सके।
 - (v) राहत एवं बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।
 - (vi) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएंगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0), दिनांक 26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। (फोटो प्रति संलग्न)।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी :
- (i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जायँ।
 - (ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाय। उक्त नियंत्रण कक्ष का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ ही उक्त नियंत्रण कक्ष में दूरभाष की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।
 - (iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मत अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।
 - (iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों में भी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहाँ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।
 - (v) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गए सुझावों के अनुरूप लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।
 - (vi) जिला पदाधिकारी निरोधात्मक कार्यवाही के संदर्भ में अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/ प्रसारित करावेंगे :-

- (क) गाँव में हवा के झोंकों के तेज होने से सुबह तक खाना पकाकर आग को पूरी तरह पानी से बुझा दें।
- (ख) आग चिंगारी पूरी तरह बुझा दी जाय।
- (ग) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।
- (घ) बीड़ी-सिगरेट पीकर इधर-उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।
- (च) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।
- (छ) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें-क्या न करें' को प्रभावी कराया जाय। (संलग्न है।)
- (vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टैंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे-छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था ग्रामीणों की मदद से की जा सकती है।
- (viii) विभागीय पत्रांक 1293, दिनांक 17.04.2012 द्वारा अद्यतन संशोधित मानदर सभी संबंधितों को निर्गत किया गया है। पुनः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-32-3/2013-NDM-1 दिनांक-21.06.2013 द्वारा मानदर के क्रम/मद सं० 1 (ड), 5 (I) B (क) एवं (ख) तथा 5 (II), 6 (II) एवं (III) तथा 9 (a) (I) में संशोधन किया गया है, जिसे विभागीय पत्रांक-4154/आ०प्र०, दिनांक-18.09.2013 द्वारा दिनांक-15.08.2013 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं (अग्निकांड सहित) के लिए लागू किया गया है।
- (ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी०आर०एफ० (अब एस०डी०आर०एफ०) से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक-1023 दिनांक-21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।
- (x) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जायेगी। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना/ झोपड़ी बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जायेगा।
- (xi) मकान/ झोपड़ी की क्षति के लिए निर्धारित मानदर के अनुरूप गृह क्षति अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक-2886 दि०-26.05.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी०पी०एल० परिवारों को

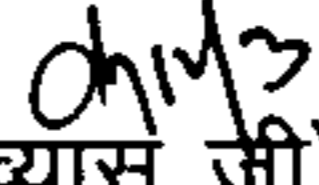
पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है।

- (xii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।
- (xiii) यदि मुख्यालय से सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों (प्रधान सचिव सहित) से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
- (xiv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन


(व्यास जी)

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
आगजनी से बचाव हेतु उपाय

क्या करें

- स्टोव या लकड़ी, गोइठा आदि के जलावन वाले चूल्हे पर खाना बनाते वक्त सावधानी बरतें। हमेशा सूती वस्त्र पहनकर ही खाना बनावें।
- गेहूँ ओसनी का काम हमेशा रात में तथा गाँव के बाहर खलिहान में जाकर करें।
- घर व खलिहान पर समुचित पानी व बालू की व्यवस्था रखें।
- खाना पकाते समय रसोईघर में वयस्क मौजूद रहें, बच्चों को अकेला न छोड़ें।
- खिड़की से स्टोव के बर्नर तक हवा न पहुँच पाए, इस बात की पूरी तसल्ली कर लें।
- सरकारी सहायता पाने के उद्देश्य से जानबूझकर अपनी सम्पत्ति में आग लगाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने में प्रशासन की मदद कर जागरूक नागरिक अवश्य बनें।
- तौलिये या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिए करें।
- तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डालें।
- तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डालें या सिर्फ बेकिंग सोडा, नमक डालें या उसे ढंक दें।
- खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ हैं और आपको मदद चाहिए।
- गैस चूल्हे का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद सिलिंडर का नॉब तुरंत बंद कर दें।
- बिजली तारों एवं उपकरणों की नियमित जाँच करें।
- घर में अग्निशमन कार्यालय तथा अन्य आपातकालिन नंबर लिखा हुआ हो और घर के सभी सदस्यों को इन नंबरों के बारे में पता हों।
- आग लगने पर दमकल विभाग को फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बतायें फिर दमकल विभाग जैसा कहें वैसा ही करें।

क्या न करें

- बच्चों को माचिस या आग फैलाने वाले एवं अन्य सामानों के पास न जाने दें।
- बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि पीकर जहाँ-तहाँ न फेंकें, उसे पूरी तरह बुझने के बाद ही फेंकें।
- चूल्हा, ढिबरी, मोमबत्ती, कपूर इत्यादि जलाकर न छोड़ें।
- अनाज के ढेर, फूस या खपड़ेल की झोपड़ी के निकट अलाव व डीजल इंजन नहीं चलाएं।
- सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएँ।
- आपके कपड़े में अगर आग लग जाए तो दौड़ना नहीं चाहिए बल्कि जमीन पर लेटकर गोल-गोल कर आग बुझावें।
- खाना बनाने के समय ढीले-ढाले कपड़े न पहनें।
- अग्नि दुर्घटना के दौरान कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें।
- गैस की दुर्गंध आने पर बिजली के स्वीच को न छुएँ।
- खाना पकाते समय रसोईघर में बच्चों को अकेला न छोड़ें।

पत्रांक-1/प्रा0आ0(2)-24/2006...1834/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 8.6.12

विषय- भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-52(प्र0) दिनांक-26.05.2012 के द्वारा भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में निदेश भेजा गया है, जिसमें पांच वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त सुबह-शाम आवश्यकतानुसार दूध मुहैया कराने का प्रावधान भी किया गया है। दूध की आपूर्ति कॉम्फेड द्वारा किया जाना है तथा वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में जिलों से पृच्छा की गई है कि बच्चों को मुहैया कराये जाने वाले दूध की मात्रा क्या होगी तथा कॉम्फेड द्वारा दूध उपलब्ध नहीं कराये जाने पर दूध का कय कहाँ से किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि राहत कैम्पों में सुबह-शाम 250-250 मि0ली0 दूध 5 वर्ष अथवा इससे कम उम्र के बच्चों को दिया जाय। कॉम्फेड द्वारा दूध नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता का दूध का कय किया जा सकता है। दूध संक्रमणमुक्त हो, इसकी जांच भी जिला पदाधिकारी करा लेंगे।

विश्वासभाजन


(व्यास जी)

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-26.05.12

विषय- भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों
संचालन के संबंध में।

महाशय,

ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की घटनायें होती रहती है। अग्निकांड की छिटपुट घटनायें होने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित गति से पीड़ितों को निर्धारित मानदर के अनुरूप सहाय्य प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु भीषण अग्निकांडों, जिसमें काफी संख्या में झोपड़ियां/कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होते हैं तथा जानमाल की गंभीर क्षति होती है, से प्रभावित परिवारों को विशेष राहत केन्द्रों में आवासित करने की आवश्यकता हो सकती है।

अतएव जिला पदाधिकारी भीषण अग्निकांडों में आवश्यकतानुसार विशेष राहत केन्द्रों की स्थापना कर सकते हैं। यह विशेष राहत केन्द्र कम अवधि के लिए चलाए जायेंगे जिसका निर्धारण स्थिति विशेष के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी राज्य आपदा रिस्पांस कोष के मानदर के अनुसार अनुदान का भुगतान शीघ्रता से सुनिश्चित करेंगे। मुफ्त साहाय्य एवं गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए ताकि पीड़ित परिवार अपने अस्थायी आवासन की व्यवस्था कर लें। तब विशेष कैम्प की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे राहत केन्द्रों के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाएगी :-

1. कैम्प कार्यालय - कैम्प कार्यालय खोलकर प्रभावित परिवारों का पंजीयन कर लिया जाय जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी दर्ज की जाय। इस कार्य हेतु हल्का कर्मचारी। पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक/आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका की सेवा ली जा सकती है
2. आवासन- घटना स्थल के समीप किसी सरकारी पक्का मकान यथा विद्यालय भवन /सामुदायिक भवन/आंगनबाड़ी केन्द्र/पंचायत भवन आदि के परिसर में अथवा टेन्टों में प्रभावित परिवारों को आवासित किया जाय। यदि टेन्ट उपलब्ध न हों तो आपदा प्रबंधन विभाग को त्वरित गति से सूचित किया जाए ताकि अन्य जिलों में उपलब्ध टेन्ट उक्त जिले में भेजवाए जाए।

3. भोजन— प्रभावित परिवारों को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह –शाम) मुहैया कराया जाना है। इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी एवं ईंधन की आवश्यकता होगी। यह प्रयास रहे कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने का कार्य यथा संभव स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी। कैम्प में आये हुए विस्थापित महिलाओं/पुरुषों की सेवायें इस कार्य हेतु ली जा सकती हैं। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर की जायेगी। पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए।

इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।

4. दरी /चटाई— विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/चटाई की व्यवस्था की जायेगी।
5. वस्त्र एवं बर्तन — विभागीय पत्रांक-1376 दिनांक-27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचरित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्तन का कय कर सकें।
6. बच्चों के लिए दूध— पाँच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह-शाम) आवश्यकतानुसार दुग्ध मुहैया कराया जाएगा।
7. रोशनी— कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। इसके लिए generator में diesel/kerosene, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा।
8. पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता— पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई के लिए साबुन/डिटजेन्ट पाउडर, फेनाईल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती हैं।
9. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा— कैम्प में औषधि के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। नये संशोधित मानदर के अनुसार चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) द्वारा दिया जाना है।
10. सुरक्षा व्यवस्था— अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायेगी।
11. संचार सुविधा— आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कैम्प में संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।
12. मानदर— कैम्प व्यवस्था हेतु मानदर निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कैम्प हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित की जाती हैं:-

1. पका हुआ भोजन	(क) दो वक्त (सुबह-शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा।
	(ख) मुफ्त वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराए गए, चावल का उपयोग राहत शिविर में किया जाएगा।
	(ग) चावल प्रति व्यस्क-500 ग्राम, प्रति अवस्क-200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा।
	(घ) दाल 100 ग्राम, व्यस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा।
	(ङ) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से।
	(च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से।
	(छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
	(ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय कय समिति द्वारा किया जाएगा।
2. रोशनी	(क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था।
	(ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारण जिला स्तरीय कय समिति द्वारा किया जाएगा।
	(ग) 1 माह में 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा।
	(घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. दरी/चादर	इसकी व्यवस्था सरकारी संख्या/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी। अनुपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार कय करने की कार्रवाई करेंगे।

4. बच्चों के लिए दुग्ध	(क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा। (ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. वस्त्र / बर्तन	(क) विभागीय पत्रांक-1376 दिनांक- 27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचारित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्तन का कय कर सके।
6. पेयजल/अस्थायी शौचालय/स्वच्छता	इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी।
7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा NRHM मद से की जायेगी।
8. संचार	शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय एस0डी0आर0एफ0 मद से अनुमान्य होगा।
9. कैम्प व्यवस्था	परिवहन तथा आकस्मिक व्यय-यथा आवश्यकता।

13. लेखा/पंजियों का संधारण- कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियों संधारित की जाएगी।

(क) लेखा संबंधित रोकड़बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबंधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे सुनिश्चित किया जाय। भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग

से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ध) कम्पेड से प्राप्त होने वाले मिल्क पाउडर के लिए स्टॉक पंजी संधारित की जाय क्योंकि कम्पेड को इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा। बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे।

(ड़) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त सामग्री का उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा-जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

कैम्प की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगा:-

क्र०सं०	मद	शीर्ष
1	भोजन सामग्री	2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति
2	दरी/चटाई एवं रोशनी	2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण
3	वस्त्र एवं बर्तन	2245-02-101-0007- क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान
4	बच्चों के लिए दूध	2245-02-800-0006-कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार
5	पेयजल	2245-02-102-0001-पेयजल की आपूर्ति
6	अस्थायी शौचालय	2245-02-109-0001-खराब जलापूर्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना
7	संचार सुविधा	2245-02-112-0004-संचार उपकरणों का क्रय

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र०)...../आ०प्र०,

पटना-15, दिनांक-26.05.12


प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-26.05.12


प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-26.05.12

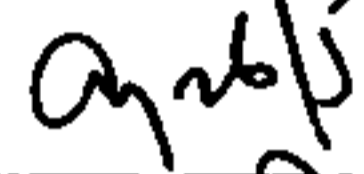
प्रतिलिपि- सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-26.05.12


प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-26.05.12

प्रतिलिपि-माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इसे माननीय मुख्य मंत्री/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के अभिज्ञान में लाया जाए।


प्रधान सचिव

प्रपत्र-I
प्रपत्र (अग्निकांड)

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्रभावित गाँवों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या			मृतकों/घायलों की संख्या			
				पूर्ण	आंशिक	योग	मनुष्य		पशु	
							मृत	घायलों की सं०	मृत	घायलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मुफ्त खाद्यान्न के लिए कुल राशि	कपड़ा/ बर्तन के लिए कुल राशि	पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के लिए कुल राशि	आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए कुल राशि	अनुग्रह अनुदान मृतकों के लिए कुल राशि	घायलों के लिए अनुदान मद में कुल राशि
12	13	14	15	16	17

प्रपत्र-II

वैश्विक वर्ष 2014 में अग्निकांड से हुई क्षति एवं वितरित साहाय्य संबंधी विवरणी

प्रभावित गांवों की सं०	प्रभावित परिवारों की सं०	क्षतिग्रस्त मकानों की सं०			क्षतिग्रस्त मकानों का अनुमानित मूल्य	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक क्षति का अनुमानित मूल्य	मृतकों की संख्या		नगद अनुदान	वितरित अनुदान	
		पूर्ण	आंशिक	योग			मनुष्य	पशु			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रभावित गांवों की सं०	चूना	गुड़	मोमबत्ती	दियासलाई	किरासन तेल	पॉलिथीन	अभ्युक्ति
17	18	19	20	21	22	23	

प्रपत्र-III

ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-2886 दि0-26.05.2005 के आलोक में प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों एवं ऐसे जले मकानों के लिए उपलब्ध कराई गई इन्दिरा आवास की सूची वर्ष 2013

जिला का नाम

प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों की अंचलवार संख्या	प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों के लिए निर्मित इन्दिरा आवास की संख्या		अभ्युक्ति
	स्वीकृत	निर्मित	
1	2	3	4

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर